DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2022 ----------DATED----------

भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी

साक्षात्कार

भाजपा के सामने एमसीडी चुनाव में चौथी बार जीत प्राप्त करने की चुनौती है। इसके लिए प्रदेश स्तर के साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी काम कर रहे हैं। चुनाव की चुनौती, पार्टी की रणनीति, मुद्दे व विरोधियों के आरोपों पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता से दैनिक जागरण के संतोष कुमार सिंह ने बात की...

● नगर निगम चुनाव में दिल्लीवासी भाजपा को क्यों समर्थन दें?

-पांच वर्ष में भाजपा ने निगम के कामकाज को पारदर्शी बनाने और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए हैं। कोरोना काल में आप और कांग्रेस के नेता घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भाजपा के नेता-कार्यकर्ता और निगमकर्मी जान की परवाह किए बिना जनसेवा कर रहे थे। जरूरतमंदों को राशन, भोजन, सैनिटाइजर बांट रहे थे। निगमकर्मी अस्पतालों व गलियों की सफाई में लगे थे। स्वच्छता को बढ़ाने के लिए पांच सौ ढलावघरों को बंद कर वहां जनरसोई, पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र बनाए गए। कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी कई कदम उठाए गए। इन्हीं कार्यों के आधार पर भाजपा जनता से समर्थन मांग रही है।

● आप और कांग्रेस निगम में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा इसका कैसे जवाब देगी?

-भाजपा भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करती है। पांच वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायत पर लगभग एक सौ अभियंताओं को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए बाध्य किया गया। भ्रष्टाचार के आरोप पर हमने अपने सात पार्षदों को पार्टी से निष्कासित किया है। कामकाज को आनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ी है। इसे और आगे बढ़ाया जाएगा।

● निगमों के एकीकरण और वार्डों के परिसीमन से भाजपा को लाभ हो रहा है या नुकसान?

-राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली के हित में निगमों का एकीकरण किया गया है। तीन निगम होने से फंड के अभाव में विकास बाधित हो रहा था। अब एकसमान विकास होगा। निगम आर्थिक रूप से मजबूत होकर बेहतर निर्णय ले सकेगा। इसका लाभ दिल्लीवासियों को मिलेगा।

● भाजपा, दिल्ली सरकार पर नगर निगम को फंड न देने का आरोप लगाती है। यदि निगम में फिर भाजपा को मौका मिला तो इसका क्या समाधान है?

-निगम के नए एक्ट में केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के पास भी कई अधिकार हैं। आठ वर्ष में दिल्ली सरकार ने निगमों को 42 हजार करोड़ रुपये नहीं दिए, जिससे कामकाज बाधित हुआ। एकीकरण से निगम मजबूत हुआ है और अब सरकार फंड नहीं रोक सकेगी।

● बागियों से कैसे निपटेंगे?

-टिकट के लिए ज्यादा दावेदारी भाजपा की लोकप्रियता का प्रमाण है। औसतन प्रत्येक वार्ड से 20 दावेदार थे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद प्रत्याशी तय किए गए हैं। यही कारण है कि विरोध के बहुत कम मामले सामने आए हैं। निर्दलीय लड़ रहे भी पार्टी हित में अपना निर्णय बदलेंगे। सभी नेता-कार्यकर्ता भाजपा को जिताने के लिए काम करेंगे।

● राजधानी के किन क्षेत्रों और वर्गों में पार्टी अपने आप को कमजोर समझती है। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

-झुग्गी बस्ती के मतदाताओं को साथ जोड़ने की चुनौती थी। अब स्थिति बदली है। लोग भाजपा से जुड़े हैं। केंद्र सरकार व भाजपा उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना से झुग्गी का वादा पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री ने 3024 लोगों को उनके फ्लैट की चाबी सौंपी है। 17 हजार फ्लैट बनकर तैयार है। इससे झुग्गी के लोग खुश हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि उनके कल्याण के लिए सिर्फ भाजपा काम करती है।

● कूड़े के पहाड़ों व नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन भुगतान में आने वाली परेशानी की समस्या कैसे दूर करेंगे?

-यह कोई मुद्दा नहीं है। आप सरकार ने आठ वर्ष में इस समस्या के हल के लिए सहयोग नहीं किया है। अब वह कूड़ा उठाने वाले सफाईकर्मियों का अपमान कर रहे हैं। प्रतिदिन 11 हजार मीट्रिक टन कूड़ा लैंडफिल साइट पर पहुंचता है। कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स बनाया और दो वर्ष से काम चल रहा है जिससे 20 फुट तक ऊंचाई कम हुई है। वर्ष 2024 तक गाजीपुर, ओखला व भलस्वा स्थित कूड़े के पहाड़ खत्म कर वहां पार्क बनाए जाएंगे। कूड़े से बिजली बनाने के चार संयंत्र लगाए गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022

RS----------DATED----------

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 18 नवंबर, 2022

Cong targets BJP on 'hollow promises'

New Delhi: Congress spokesperson Alka Lamba on Thursday said BJP had made many hollow promises in its manifesto to mislead Delhiites. Many of these issues don't come under the purview of Municipal Corporation of Delhi (MCD), the former MLA alleged.

While BJP has said it is giving good flats to residents of JJ clusters who had been fooled by Congress for decades, Lamba alleged that the BJP and AAP governments were not even providing basic amenities to nearly 20 lakh people living in over three lakh slums across the capital. "BJP, in collusion with AAP, had made a scheme to rent out 46,000 flats, the construction of which was started by the Congress government," claimed Lamba.

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said that like AAP, Congress was also frustrated by the Centre's time-bound delivery of 3,024 flats to jhuggi dwellers. "Congress' Alka Lamba should know that BJP's Vachan Patra does not say that MCD will make flats for jhuggi dwellers, it is BJP's commitment that it will identify jhuggi clusters where flats will be made and delivered by central government agencies like DDA," he added.

Lamba promised that Congress would make Delhi green, clean, progressive and developed once again. TNN

पर्यावरण विभाग की मंजूरी नहीं मिलने से अटकीं 10 परियोजनाएं

राज्य, नई दिल्ली: राजधानी में यातायात सुगम बनाने के लिए द्वारका एक्सप्रेस-वे सहित 10 परियोजनाएं पर्यावरण विभाग की मंजूरी न मिलने से तीन साल से लंबित हैं। एलजी वीके सक्सेना ने यह मुद्दा साप्ताहिक बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि विकास की इन योजनाओं को जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक, एलजी ने सीएम से कहा है कि ये परियोजनाएं शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें यातायात को सुचारु बनाने और सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराने के लिए सड़कों के निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग और आवासीय परिसरों की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ 2019 से लंबित हैं। इन परियोजनाओं के लिए मुआवजे के रूप में धन और डीडीए द्वारा अनिवार्य वनीकरण के लिए जमीन समेत सभी जरूरी शर्तें पूरी की गई हैं। इस बाबत 17 व 30 सितंबर को सीएम को पत्र भी लिखा गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
PERS
नई दिल्ली
शुक्रवार
18 नवंबर 2022

मेरी आवाज सुनो

समस्या : पार्किंग

निगम चुनाव की घोषणा के बाद से ही दलों ने वादों की झड़ी लगा दी है, पर अभी तक कुछ पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पार्किंग से लेकर साफ-सफाई, अवैध निर्माण से लगाने वाले जाम और आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी से लोग रोज जूझते हैं। इन्हीं दिक्कतों को 'मेरी आवाज सुनो' के तहत आपका अपना अखबार 'हिन्दुस्तान' उठाएगा।

दिल्ली में सवा करोड़ वाहनों के लिए सिर्फ सवा लाख पार्किंग

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में कोई भी चुनाव हो, पार्किंग प्रमुख मुद्दा रहता है। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग सवा करोड़ पहुंच चुकी है, लेकिन यहां वाहनों की पार्किंग क्षमता बमुश्किल सवा लाख है।

सड़कों पर अवैध पार्किंग, गलियों में घरों-पार्कों के बाहर और बाजारों में खड़े वाहनों के कारण लोगों को जाम और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में पार्किंग संचालन का काम एमसीडी, डीडीए, दिल्ली मेट्रो समेत अन्य सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है।

रोज पंजीकृत होते हैं 1200 वाहन : परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 1200 से 1500 वाहनों का पंजीकरण किया जाता है। दिल्ली में वाहन पंजीकरण की संख्या 1 करोड़ 20 लाख को पार कर चुकी है। इनमें दोपहिया और चार पहिया समेत मालवाहक वाहन भी शामिल हैं। दिल्ली की सड़कों से वाहन कम करने के लिए सरकारों की ओर से लगातार मेट्रो और सार्वजिनक बसों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण पार्किंग की समस्या जस की तस बनी हुई है।

लोग कर रहे मंथन : निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की हार-जीत और पूर्व में हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। करोलबाग के न्यू रोहतक रोड कॉलोनी में विभिन्न आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और सदस्य गुरुवार को निगम चुनाव पर मंथन करते दिखे। आरडब्ल्यूए महासचिव गगन बेदी ने कहा कि करोलबाग में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की बहुत समस्या है। लोग यहां खरीदारी के लिए आते हैं, जिन्हें पार्किंग की परेशानी से जूझना पड़ता है। देवनगर से पहुंचे चंद्रशेखर ने कहा कि उनके क्षेत्र में सीवेज की समस्या है।

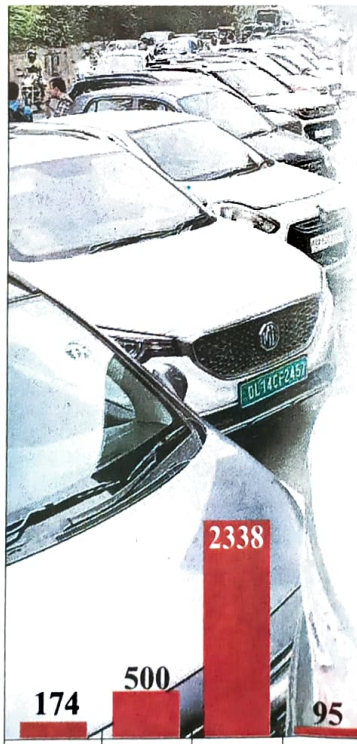

किसकी कितनी पार्किंग क्षमता

56 हजार वाहनों की क्षमता दिल्ली में निगम की पार्किंग में

10-12 हजार वाहनों के पार्किंग की क्षमता दिल्ली मेट्रो की

05 से छह हजार वाहनों के पार्किंग की क्षमता डीडीए की

08-10 हजार वाहनों की पार्किंग क्षमता एनडीएमसी की

अन्य विभागों की भी कुछ पार्किंग हैं

उम्मीद : दिसंबर अंत तक बढ़ेगी क्षमता

निगम के अनुसार, जून 2023 तक दिल्ली को नौ पार्किंग मिल जाएंगी। इसमें छह पार्किंग इसी साल दिसंबर अंत तक मिलने की उम्मीद है। निगम के अनुसार, छह पार्किंग जिनकी क्षमता 3324 वाहनों के खड़े करने की होगी उनको दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को इन पार्किंगों को समर्पित कर दिया जाएगा। दिसंबर तक निगम की चांदनी चौक की 2338 क्षमता की पार्किंग का कार्य पूरा हो सकता है। इसी प्रकार पजल तकनीक से युक्त निजामुद्दीन की छह मंजिला पार्किंग जिसकी क्षमता 86 कारों की होगी वह भी शुरू होगी। अमर कॉलोनी लाजपत नगर, शिवा मार्केट प्रीतमपुरा, निगमबोध घाट और फतेहपुरी स्थित पार्किंग का कार्य दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

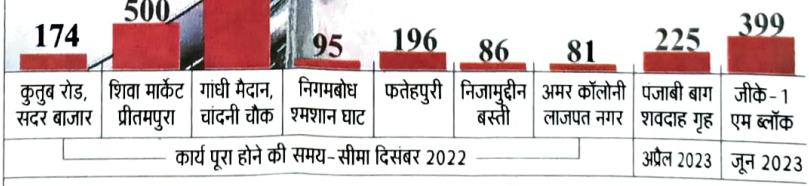

लोग बोले

"हाईकोर्ट के वकीलों के लिए गाड़ी पार्किंग की काफी दिक्कतें हैं। अभी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में 28 हजार सदस्य हैं पर उनके वाहनों की पार्किंग के लिए बहुत कम जगह है। - **एडवोकेट जतन सिंह**, उपाध्यक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन

"सदर बाजार राजधानी का प्रमुख बाजार है, लेकिन यहां पर व्यापारी अपनी गाड़ी से नहीं आ सकता है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पार्किंग की समस्या का समाधान हो। - **परमजीत सिंह पम्मा**, चेयरमैन, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन

"कई कॉलोनियों में वाहन पार्किंग के लिए बिलकुल जगह नहीं बची है। गली-मोहल्लो में आए दिन इसे लेकर झगड़े होते हैं। निगम को खाली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा पार्किंग बनानी चाहिए। - **जयंत सामल**, बिजनेसमैन

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

नई दिल्ली। शुक्रवार • 18 नवम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

सरकार की निष्क्रियता से नजफगढ़ नाले में 85 लाख मीट्रिक टन गाद जमा : एलजी सचिवालय

नई दिल्ली (एसएनबी)। नजफगढ़ नाले की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के रवैए पर उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नाराजगी जताई है। सूत्रों की मानें तो नजफगढ़ नाले की सफाई को लेकर सरकार लगातार उदासीन है। शायद यही वजह है कि नाले में करीब 85 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा होकर उसका एक जगह टीला बन गया है। इससे नाले के पानी के बहाव में कमी आई है। नालों की सफाई के विशेषज्ञों की मानें तो इस ग़ाद को एक साथ निकाला जाए, तो यह गाजीपुर लैंड फिल साइट पर जमा 85 लाख मीट्रिक टन कूड़े के बराबर है। हालांकि उप-राज्यपाल की सक्रियता के चलते गाद निकालने का काम तेज हुआ है और तिमारपुर से मॉल रोड ब्रिज तक का करीब 2 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह साफ हो गया है। उप-राज्यपाल सचिवालय ने इसके निरीक्षण के फोटो भी जारी किए हैं।

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि बीते 17 साल से नालों की सफाई/ गाद निकालने के लिए कोई नया यंत्र नहीं मिला है। नाले में गाद के इस टीले की वजह से पानी का प्रवाह धीमा पड़ गया है। यही वजह है कि बरसात के दौरान पानी जमा होने से आसपास के नाले ओवरफ्लो होकर जलभराव का रूप ले लेते हैं। करीब 57 किलोमीटर लंबे इस नाले में छोटे-बड़े कुल 121 नाले गिरते हैं। नाले में गाद की वजह से यहां आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण भी बढ़ जाता है। सूत्रों का दावा है कि यमुना में प्रदूषण के बढ़ते स्तर का यह एक बड़ा कारण बनता है। नाले की सफाई को लेकर बीते पांच-छह महीने में काम तेज हुआ है। नालों की सफाई पर उप-राज्यपाल लगातार ध्यान दे रहे हैं। नालों की सफाई को लेकर वह दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए एवं दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं।

'सरकार के पास लंबित कई प्रस्ताव'

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में यातायात को सुगम एवं पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए तैयार किए गए कई प्रस्ताव पर्यावरण विभाग के पास लंबित हैं। इसके साथ ही नई सरकारी आवासीय कालोनियों के निर्माण के का मामला की सरकार की उदासीनता के चलते लटका हुआ है। सूत्रों की मानें तो इस तरह के कुल 10 प्रस्ताव हैं, जो दिल्ली सरकार के पास लंबित हैं। इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी के लिए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बीते 17 अगस्त एवं 30 सितम्बर को पत्र भी लिखे थे। इन पत्रों की पुष्टि उप-राज्यपाल सचिवालय ने की है। सूत्रों का कहना है कि कुछ प्रस्ताव तो वर्ष 2019 से लंबित हैं। मुख्यमंत्री के साथ होने वाली साप्ताहिक बैठकों में यह मामला उप-राज्यपाल ने उठाया और प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया था। उप-राज्यपाल सचिवालय का कहना है कि साफ तौर पर इसमें सरकार के स्तर पर निष्क्रियता नजर आती है।